





















सकती थी। केंद्र सरकार ने कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 100 करोड़ रुपए की अनुदान राशि भी दी थी। लेकिन कांग्रेस सरकार ने वह राशि वापस कर प्रदेश के हजारों युवाओं के रोजगार के अवसर छीन लिए। उन्होंने आरोप लगाया कि चार वर्षों तक परियोजना स्थल पर केवल औपचारिक गतिविधियाँ होती रही और अब सरकार 20 हजार करोड़ रुपये के टर्नओवर जैसे खोखले दावे कर रही है। अनेक खनन के मुद्दे पर बिक्रम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में खनन माफिया इसलिए बेखोज है क्योंकि उसने उस सत्ता से जुड़े लोगों का संरक्षण प्राप्त है।

